अनुलग्नक–1

हालिया राजनीतिक–आर्थिक घटनाक्रम पर टिप्पणी

हाल का दौर तीव्र भू–राजनीतिक बदलावों का दौर रहा है। निस्संदेह, अमेरिका–इजराइल आक्रामकता के विरुद्ध ईरान के बहादुराना प्रतिरोध ने विश्व राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। यदि ईरान को बिना किसी प्रतिरोध के अमेरिका द्वारा हरा दिया जाता, तो ग्लोबल साउथ की जनता पर साम्राज्यवादी आक्रमण और भी भयावह रूप ले लेता। मोदी सरकार का अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रति खुला समर्पण तथा इजराइल के साथ उसका कुख्यात गठबंधन भारत की जनता के लिए गंभीर कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भारत को रूस से सस्ता ईंधन प्राप्त करने से भी रोका।

हॉर्मुज की खाड़ी की नाकेबंदी ने पहले ही एक बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि वैश्विक LNG आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत बाधित हो चुका है, जिसके कारण एशिया और यूरोप में गैस की कीमतें 2023 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई हैं। तेल बाजार की अस्थिरता के कारण मार्च 2026 में कीमतों को स्थिर करने के लिए सामरिक भंडारों से लगभग 40 करोड़ बैरल तेल जारी करना पड़ा। IEA के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने इस स्थिति को "संभवतः अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट" बताया है।

विश्व बैंक ने 2026 में ऊर्जा कीमतों में 24 प्रतिशत और उर्वरक कीमतों में 31 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि तेल की कीमतें औसतन लगभग 86 डॉलर प्रति बैरल रहने की संभावना है। इन घटनाक्रमों के कारण दुनिया भर में ईंधन, परिवहन, बिजली और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे मजदूरों और गरीब जनता के लिए जीवन–यापन का संकट और गहरा गया है।

इसी के साथ वैश्विक स्तर पर महँगाई बढ़ी है जबकि मजदूरी ठहरी हुई है। अमेरिका और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन यानिकि मंदी तेजी से बढ़ रहा है। IMF ने 2026 में वैश्विक वृद्धि दर लगभग 3.1 प्रतिशत रहने तथा महँगाई के नए दबावों का अनुमान लगाया है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों में ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें सीधे वास्तविक मजदूरी और क्रयशक्ति को कम कर रही हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण विकास सैन्यीकरण और रक्षा व्यय में तीव्र वृद्धि है। बढ़ते सैन्य खर्चों के कारण विश्वभर में सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। जब सरकारें युद्ध की तैयारियों और सामरिक प्रतिस्पर्धा पर सार्वजनिक संसाधन खर्च कर रही हैं, तब स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सब्सिडी और रोजगार कार्यक्रमों पर होने वाला सामाजिक व्यय निरंतर दबाव में आ रहा है।

इसी समय, धीमी आर्थिक वृद्धि के बीच लाभ बढ़ाने की लालसा में विभिन्न क्षेत्र की कंपनियाँ स्वचालन और AI–आधारित पुनर्गठन को तेज कर रही हैं। लेकिन चार "हाइपरस्केलर" कंपनियों–अमेजन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा–का संयुक्त मुक्त नकदी प्रवाह 2014 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुँचने की ओर है। AI बुलबुले के फूटने की स्थिति में इसका वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही छँटनी, अस्थिर रोजगार, श्रम का अनौपचारिकीकरण और कार्यभार की तीव्रता वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। तकनीकी विस्थापन यानि तकनीकी प्रगति के चलते नौकरियों का खत्म होने की यह नई लहर मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता को कमजोर कर रही है।

समग्र रूप से वर्तमान वैश्विक स्थिति युद्ध–प्रेरित महँगाई, बढ़ती असमानता, सैन्यीकरण, ऋण अस्थिरता और श्रमिक अधिकारों पर हमलों से चिह्नित पूँजीवाद के गहराते संकट को दर्शाती है।

एक ओर वैश्विक संपत्ति का अभूतपूर्व केंद्रीकरण है और दूसरी ओर मजदूरों की असुरक्षा लगातार बढ़ रही है। ये परिस्थितियाँ विभिन्न देशों में मजदूरों और किसानों के बीच खर्चों में कटौती, निजीकरण और कॉरपोरेट वर्चस्व के विरुद्ध श्रमिक असंतोष, हड़तालों और संयुक्त संघर्षों को और तीव्र करेंगी।

ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की "संयम और खर्च कटौती" की नैतिक अपील वस्तुतः वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत की गहराती आर्थिक कमजोरियों की स्वीकृति है। महिंद्रा समूह के CEO एवं MD अनीश शाह और कोटक बैंक के संस्थापक उदय कोटक जैसे भारतीय पूँजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों के बयान तथा शेयर बाजारों की प्रतिक्रियाएँ पूँजी के भय, घबराहट और निराशा को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।

भारत का आर्थिक विकास मॉडल संरचनात्मक रूप से आयातित ऊर्जा, अस्थिर वैश्विक वित्त और दबे हुए घरेलू उपभोग पर निर्भर बना हुआ है। इसलिए वर्तमान संकट केवल बाहरी कारणों से उत्पन्न नहीं हुआ है। युद्ध ने केवल उन अंतर्विरोधों को उजागर किया है जो पहले से ही भारत की नवउदारवादी पूँजीवादी विकास प्रक्रिया में निहित थे।

हाल ही में बढ़ती तेल कीमतों और पूँजी पलायन के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर लगभग रू0 96 प्रति डॉलर तक गिर गया। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर इस गिरावट को धीमा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह केवल अस्थायी उपाय है क्योंकि भंडार सीमित हैं और लगातार हस्तक्षेप उन्हें धीरे–धीरे समाप्त करता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 के लगभग 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से घटकर मई 2026 तक लगभग 690.7 अरब डॉलर रह गया है। चूँकि भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85 प्रतिशत आवश्यकता आयात करता है, इसलिए लंबे समय तक ऊँची तेल कीमतें डॉलर की माँग बढ़ाकर रुपये को और कमजोर करती हैं।

इससे भारत के बाह्य खाते पर तत्काल दबाव उत्पन्न हुआ है। IMF के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा (CAD) आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए 2027 तक GDP के लगभग 1.6 प्रतिशत यानी लगभग 81 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। भारत अब भी कच्चे तेल, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और औद्योगिक मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। पेट्रोलियम आयात अब भी आयात बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि कुछ तिमाहियों में गैर–तेल व्यापार घाटे का लगभग 85–90 प्रतिशत हिस्सा सोने के आयात से बनता है। वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि के साथ बढ़ती आयात लागत और रुपये के अवमूल्यन का संयुक्त दबाव राजकोषीय घाटे तथा भुगतान संतुलन दोनों के लिए खतरा बनता जा रहा है।

भारत का व्यापारिक घाटा लगातार नकारात्मक बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को फिलहाल "अदृश्य" आय – सॉफ्टवेयर निर्यात, प्रवासी भारतीयों की धनराशि और व्यावसायिक सेवाओं – से अस्थायी सहारा मिल रहा है। भारत का अदृश्य अधिशेष लगभग 7.88 प्रतिशत के आसपास है, जो लगभग 9.18 प्रतिशत के व्यापारिक घाटे की आंशिक भरपाई करता है। लेकिन यही भारतीय पूँजीवाद की विकृत संरचना को उजागर करता है। घरेलू माँग पर आधारित व्यापक औद्योगीकरण विकसित करने के बजाय भारत का नवउदारवादी मॉडल लगातार सेवा निर्यात और वैश्विक पूँजी प्रवाह पर निर्भर होता जा रहा है।

औद्योगिक गतिविधियाँ स्वयं असमान और कमजोर बनी हुई हैं। अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स असेम्बली और पूँजी–गहन विनिर्माण में समय–समय पर वृद्धि के बावजूद रोजगार सृजन अत्यंत कमजोर रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में लगातार अस्थिरता दिखाई दी है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग निजी निवेश के सतत विस्तार के लिए आवश्यक स्तर से नीचे बना हुआ है। बहुचर्चित "मेक इन इंडिया" रणनीति श्रम–प्रधान औद्योगीकरण को आवश्यक पैमाने

पर विकसित करने में विफल रही है। विकास ऐसे क्षेत्रों में केंद्रित हो गया है जो बड़े मुनाफे तो पैदा करते हैं, लेकिन व्यापक रोजगार नहीं।

उपभोग के दृष्टिकोण से देखने पर यह अंतर्विरोध और भी तीखा हो जाता है। यह रेखांकित करना आवश्यक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तक महामारी के झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाई है, जबकि 2008 के संकट की प्रतिध्वनियाँ अब भी मौजूद थीं। मोदी की मितव्ययिता की अपील ऐसे समय आई है जब जन–उपभोग पहले से ही गंभीर दबाव में है। पिछले दशक में घरेलू उपभोग व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। ईंधन खपत के रुझान तथाकथित आर्थिक सुधार के असमान वर्गीय चरित्र को दर्शाते हैं – एविएशन टर्बाइन फ्यूल की खपत डीजल की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ी, जो यह दिखाता है कि सुधार मुख्यतः उच्च आय वर्ग की गतिशीलता पर आधारित है, न कि व्यापक उत्पादक विस्तार पर। डीजल की माँग, जो माल परिवहन, कृषि और मेहनतकश जनता की आर्थिक गतिविधियों से अधिक जुड़ी है, बहुत धीमी गति से बढ़ी है।

इसी समय घरेलू वित्तीय संकट और गहरा हुआ है। RBI के आँकड़ों के अनुसार घरेलू ऋण GDP के लगभग 42 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व स्तर है। इसका बड़ा हिस्सा उत्पादक निवेश के बजाय असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण और उपभोग आधारित उधार में केंद्रित है। साथ ही घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत में तेज गिरावट आई है, जो पहले के 7–8 प्रतिशत स्तर से घटकर लगभग 5 प्रतिशत GDP के करीब पहुँच गई है। खाद्य, ईंधन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा में महँगाई ने वास्तविक आय को लगातार कम किया है। मजदूरों और निम्न मध्यवर्ग के बड़े हिस्से अब केवल रोजमर्रा की खपत बनाए रखने के लिए ऋण पर निर्भर होते जा रहे हैं।

मोदी सरकार ने अब मजदूर वर्ग के मध्य और उच्च तबकों पर भी हमला शुरू कर दिया है। महामारी के बाद भारत का नवउदारवादी मॉडल मुख्यतः इसी आबादी के उपभोग पर आधारित रहा है। महामारी के बाद इस तबके की आय हिस्सेदारी घटी और ठहर गई है तथा पूर्व–कोविड स्तर तक भी नहीं पहुँच पाई है। इस वर्ग पर और अधिक मितव्ययिता थोपने से भारत का उपभोग बाजार और सिकुड़ेगा तथा अर्थव्यवस्था गहरे संकट की ओर धकेली जाएगी। दूसरी ओर, जबकि मेहनतकश जनता से "त्याग" की अपील की जा रही है, कॉरपोरेट मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊर्जा, अवसंरचना, दूरसंचार, लॉजिस्टिक्स और वित्त क्षेत्रों के बड़े कॉरपोरेट समूह रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज कर रहे हैं। कर रियायतें, निजीकरण, श्रम लचीलीकरण और उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने सार्वजनिक संसाधनों को और अधिक कॉरपोरेट पूँजी की ओर स्थानांतरित किया है।

आज भारत में पूँजी संचय लगातार श्रम लागत को दबाने, श्रमिक सुरक्षा को कमजोर करने, अनौपचारिकीकरण तथा राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक संपदाओं की लूट पर निर्भर होता जा रहा है। लेकिन इससे लोगों का विस्थापन होता है और जन–क्रयशक्ति कमजोर पड़ती है, जिससे स्थिर औद्योगिक विस्तार के लिए आवश्यक घरेलू बाजार सीमित हो जाता है। परिणामस्वरूप, अल्प–उपभोग और पूँजी के अति–संचय का संयुक्त संकट उत्पन्न हो रहा है।

इन परिस्थितियों में मितव्ययिता या खर्च कटौती वह राजनीतिक भाषा बन जाती है जिसके माध्यम से संकट का बोझ मेहनतकश जनता पर डाला जाता है। मजदूरों से कम उपभोग करने को कहा जाता है जबकि कॉरपोरेट लगातार अधिक संचय करते रहते हैं। सार्वजनिक कल्याण व्यय में कटौती की जाती है जबकि पूँजी को प्रोत्साहन बढ़ाए जाते हैं। राज्य इस अंतर्विरोध को केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी नियंत्रित करता है– बढ़ती तानाशाही, श्रमिक संघर्षों के दमन, निगरानी और असहमति के अपराधीकरण के माध्यम से। मूलतः यही नव–फासीवादी परियोजना का विस्तार है।

इस प्रकार मोदी का मितव्ययिता संबंधी भाषण केवल अस्थायी वैश्विक उथल–पुथल पर चिंता का प्रतीक नहीं है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि भारत का नवउदारवादी विकास मॉडल अब स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ होता जा रहा है, जब तक कि वह मजदूरों और आम जनता से लगातार बलिदान की माँग न करे।

यह निश्चित है कि गहराता संकट वर्गीय अंतर्विरोधों को और तीखा करेगा तथा सामाजिक संघर्षों को जन्म देगा। उत्तर और मध्य भारत में गैर–नियमित श्रमिकों का वीरतापूर्ण उभार इस स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये उभार भले ही अधिकांशतः स्वतःस्फूर्त रहे हों, लेकिन उन्होंने पूरे देश के मजदूरों में उत्साह पैदा किया है। संकट की गहराई, विशेषकर LPG संकट, मजदूरों को लगातार निर्वाह स्तर से नीचे धकेलती जाएगी। इसलिए ऐसे प्रतिरोध और उभार आगे भी उभरते रहेंगे और केवल NCR क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे।

इन घटनाक्रमों के बीच भारत में चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए। निस्संदेह, चुनाव परिणाम मेहनतकश वर्ग और आम जनता के लिए एक झटका साबित हुए हैं। हमने अपना अंतिम गढ़ – केरल की LDF सरकार को खो दिया है। जनपक्षीय विकास के उत्कृष्ट कार्यों के बावजूद, जटिल वैश्विक और राष्ट्रीय परिस्थितियों में LDF सरकार को बरकरार नहीं रखा जा सका। अब केरल के मेहनतकश वर्ग के लिए श्रमिक–विरोधी UDF सरकार के विरुद्ध अपने हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाना और कठिन होगा।

दूसरी ओर, भाजपा ने उग्र साम्प्रदायिकता और चुनाव आयोग सहित समस्त राज्य मशीनरी के घोर दुरुपयोग के बल पर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल कर ली है। जीत के तुरंत बाद भाजपा सरकार ने झुग्गियों को ध्वस्त करना, अल्पसंख्यकों और प्रगतिशील आवाजों पर हमला करना, गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के नाम पर समाज में फूट डालना और भूमि–सीमा कानूनों को समाप्त करना शुरू कर दिया। अब राज्य–प्रायोजित कॉरपोरेट आक्रमण, जनता पर हमले और उग्र साम्प्रदायिकीकरण का व्यापक दौर चलेगा। असम में भाजपा सरकार बनी हुई है, जबकि तमिलनाडु की धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील सरकार को भी हटा दिया गया है। हालाँकि नई TVK–नेतृत्व वाली सरकार भी धर्मनिरपेक्ष रुख अपनाती दिखाई दे रही है।

यह व्यापक रूप से अपेक्षित था कि पश्चिम बंगाल में जीत के तुरंत बाद भाजपा श्रम संहिताओं को लागू करेगी। हम अब एक ऐसे नए श्रम शासन में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ न्यूनतम कानूनी सुरक्षा तक वापस ले ली गई है। हमें इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने कार्य को पुनर्गठित और पुनर्परिभाषित करना होगा।

निश्चित रूप से वैश्विक संकट तीव्र हो रहा है, यह ऊर्जा, उर्वरक और खाद्य संकट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट की ओर धकेल रहा है। मोदी सरकार इस संकट का बोझ मेहनतकश जनता पर डालना चाहती है – मितव्ययिता थोपकर, श्रम कानूनों को समाप्त कर तथा असीमित शोषण लागू करके। राष्ट्रीय संपत्तियों, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ तक कि अंडमान–निकोबार द्वीपों की भी लूट, इस सरकार की हताशा को उजागर करती है। कठोर राज्य दमन और उग्र साम्प्रदायिकीकरण ही नव–फासीवादियों के हाथों में बचे अंतिम हथियार हैं।

हमें इस चुनौती का साहसपूर्वक सामना करना होगा; अपने संगठन को मजबूत करना होगा; अपनी यूनियनों की रक्षा करनी होगी; यूनियन समितियों को पुनर्जीवित करना होगा; सभी सदस्यों को आंदोलनकारी गतिविधियों में सक्रिय करना होगा; धैर्यपूर्वक अपनी राजनीति को मजदूरों तक पहुँचाना होगा; और इस प्रकार अपने संगठन का विस्तार करना होगा। हमें हर समय सड़कों पर न केवल मौजूद बल्कि विजिबल रहना होगा। आइए, हम इस चुनौती को स्वीकार करने और अपने 10वें सम्मेलन की भावना के अनुरूप पूरे फेडरेशन को उसी दिशा में सक्रिय करने के लिए स्वयं को तैयार करें।